# भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी: टस्क दौरे का महत्व

## खबरों में क्यों

### 28 अक्टूबर: संयुक्त वक्तव्य के आधार पर स्थिति स्पष्ट

**समाचार-संदर्भ: 22 अक्टूबर 2026 का संयुक्त वक्तव्य; यह स्पष्टीकरण 28 अक्टूबर 2026 को जोड़ा गया। मूल प्रकाशन: 22 अक्टूबर 2026।** आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का भारत दौरा 21-23 अक्टूबर था। नीचे के पुराने कार्यक्रम-संदर्भ को अब सम्पन्न दौरे की पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ें, आगामी कार्यक्रम के रूप में नहीं।

**भारत-EU FTA की स्थिति:** वक्तव्य 27 जनवरी 2026 के भारत-EU शिखर सम्मेलन के संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता सम्पन्न होने का उल्लेख करता है और उसके शीघ्र हस्ताक्षर, अनुसमर्थन तथा समयबद्ध अमल का आह्वान करता है। वार्ता सम्पन्न होना, हस्ताक्षर होना और अमल में आना अलग चरण हैं। इसलिए नीचे की पुरानी प्रेस-रिपोर्ट में दिसंबर में हस्ताक्षर की अपेक्षा को तय या सम्पन्न घटना न समझें; 22 अक्टूबर के संयुक्त वक्तव्य ने हस्ताक्षर की निश्चित तारीख नहीं दी।

**व्यापार का लक्ष्य, आधार-राशि नहीं:** 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य आधिकारिक वक्तव्य में है। नीचे का लगभग 6 अरब डॉलर का आँकड़ा पुरानी प्रेस-रिपोर्ट का है; उसे इस वक्तव्य से स्वतंत्र रूप से पुष्ट मौजूदा आधार-राशि नहीं माना गया है। दोनों विवरण अपनी स्रोत-सीमा के साथ सुरक्षित हैं।

**प्रस्ताव और उपलब्धि में अंतर:** गोपनीय सूचना संरक्षण समझौते पर जल्द हस्ताक्षर की अपेक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर बातचीत को सम्पन्न समझौता न मानें। रणनीतिक साझेदारी की परीक्षा इस बात से होगी कि संवाद, निवेश और तकनीकी सहयोग समयबद्ध परिणामों में कितना बदलते हैं।

**प्राथमिक स्रोत:** भारत-पोलैंड संयुक्त वक्तव्य, 22 अक्टूबर 2026। नीचे पुराने प्रेस-संदर्भ और उनके आँकड़े हटाए बिना रखे गए हैं।

**पुराने दौरा-पूर्व कार्यक्रम और प्रेस-संदर्भ:** आगे के संबंधित खंडों में प्रयुक्त भविष्यकाल तत्कालीन रिपोर्ट का है। अद्यतन आधिकारिक स्थिति ऊपर और संयुक्त वक्तव्य वाले खंड में पढ़ें।

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली पहुँचे। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता कार्यक्रमित है और 23 अक्टूबर को वे बेंगलुरू जाएँगे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह 16 वर्षों में किसी पोलिश प्रधानमंत्री का पहला भारत दौरा है। टस्क 2010 में (पूर्व कार्यकाल में) और 2017 में (यूरोपीय परिषद अध्यक्ष के रूप में) भारत आ चुके हैं [प्रेस]। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दौरा व्यापार-निवेश, रक्षा, उभरती तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और जन-संपर्क में सहयोग आगे बढ़ाएगा (द हिंदू में उद्धृत)।

## संबंधों की पृष्ठभूमि

- भारत और पोलैंड ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए; 2024 में 70 वर्ष पूरे हुए [विदेश मंत्रालय अभिलेख]।
- अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर पर उठाया [विदेश मंत्रालय अभिलेख]।
- मध्य और पूर्वी यूरोप में पोलैंड भारत का महत्वपूर्ण साझी है और यूरोपीय बाजारों तक पहुँच का संभावित द्वार माना जाता है।

## वार्ता के प्रमुख एजेंडे (प्रेस रिपोर्टों के अनुसार)

- व्यापार। द हिंदू के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग 6 अरब डॉलर है, जिसे दोगुना करने का लक्ष्य है; दिसंबर में भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के हस्ताक्षर की उम्मीद इसे बल देगी। 16 दिसंबर को ब्रुसेल्स में भारत-EU शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के जाने की उम्मीद है [प्रेस]।
- रक्षा। इंडियन एक्सप्रेस के साक्षात्कार में वित्त मंत्री आंद्रेज़ दोमांस्की ने कहा कि पोलैंड अपनी रक्षा-आधुनिकीकरण पर GDP का लगभग 5 प्रतिशत खर्च कर रहा है और अपने रक्षा उद्योग के लिए भारतीय साझेदार चाहता है; उन्होंने WB Group जैसी कंपनियों का उल्लेख किया [प्रेस]। द हिंदू के अनुसार दोनों पक्ष गोपनीय सूचना संरक्षण पर एक समझौते (रूस को तकनीक-रिसाव की चिंता और दोहरे-उपयोग वस्तुओं की निगरानी के मद्देनज़र) को अंतिम रूप दे रहे हैं; रक्षा संयुक्त कार्यसमूह सितंबर में वारसौ में मिला था [प्रेस]।
- स्वच्छ ऊर्जा। पोलैंड बड़े परमाणु संयंत्रों और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) दोनों में विदेशी निवेश चाहता है (दोमांस्की, IE) [प्रेस]।
- यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन से सटी सीमा के कारण संघर्ष वार्ता के केंद्र में रहा; दोमांस्की के अनुसार पोलिश पक्ष के लिए भारत के साथ "विश्वास बनाना" सबसे बड़ा कार्य है [प्रेस]।
- व्यापार-प्रतिनिधिमंडल (प्रेस-रिपोर्ट)। द हिंदू (22 अक्टूबर) के अनुसार पोलिश प्रतिनिधिमंडल दिल्ली और बेंगलुरू में रेल परिवहन, स्वच्छ-कोयला और खनन क्षेत्रों में सहयोग पर भारतीय व्यवसायों से जुड़ा; 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री टस्क ने बेंगलुरू में भारत-पोलैंड बिज़नेस फ़ोरम को संबोधित किया [प्रेस]।
- यूक्रेन पर भारत का प्रस्ताव (प्रेस-रिपोर्ट)। द हिंदू (सुहासिनी हैदर, 22 अक्टूबर) के अनुसार भारत मॉस्को और क्यीव दोनों के संपर्क में है; रिपोर्ट में प्रस्ताव के तीन तत्व बताए गए हैं — नागरिकों पर हमले बंद करना, काला सागर से दोनों देशों के अनाज और ऊर्जा निर्यात की अनुमति, और जहाज़ों व नाविकों को निशाना बनाना बंद करना (इन हमलों में कई भारतीय नाविक प्रभावित हुए हैं)। अधिकारियों ने "मध्यस्थता" से इनकार किया है; विवरण सार्वजनिक नहीं [प्रेस]। अलग संदर्भ: यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने अक्टूबर की शुरुआत में बताया था कि युद्ध-विराम के चार अलग-अलग प्रस्ताव (भारत, अमेरिका, मिस्र और तुर्किये के) विचाराधीन हैं और भारत का प्रस्ताव "सबसे व्यापक" है (इंडियन एक्सप्रेस, 2 अक्टूबर; द प्रिंट, 4 अक्टूबर) — ये चार प्रस्ताव अलग-अलग देशों के हैं [प्रेस]।

## PIB का संयुक्त वक्तव्य (22 अक्टूबर 2026): आधिकारिक बिंदु

- व्यापार और कृषि। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा। कृषि पर द्विपक्षीय कार्य-समूह की गतिविधियाँ फिर शुरू करने पर सहमति बनी। भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर और अनुसमर्थन का आह्वान किया गया।
- रक्षा। रक्षा पर संयुक्त कार्य-समूह की 8वीं बैठक (वारसॉ, सितंबर 2026) के परिणामों का स्वागत किया गया और "रक्षा उद्योग संवाद" का प्रस्ताव रखा गया। गोपनीय सूचना के पारस्परिक संरक्षण और आदान-प्रदान पर समझौते के "जल्द" हस्ताक्षर होने की अपेक्षा जताई गई; यानी वह अभी हस्ताक्षरित नहीं है।
- प्रौद्योगिकी और खनिज। AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर संयुक्त शोध तथा स्टार्टअप साझेदारी पर सहमति बनी। भू-विज्ञान, खनन और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता-ज्ञापन "बातचीत के अधीन" है।
- संपर्क। सीधी उड़ानें बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए नागरिक उड्डयन अधिकारियों को सीधी बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया गया; IMEC का उल्लेख हुआ; ध्रुवीय मामलों में वैज्ञानिक सहयोग पर सहमति बनी।

- बहुपक्षीय मंच। पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में भारत की सदस्यता और 2028-29 के अस्थायी सदस्यता दावे के लिए समर्थन दोहराया। भारत ने पोलैंड को इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया; पोलैंड के आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल होने की घोषणा का भारत ने स्वागत किया।
- सुरक्षा। यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताते हुए "व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति" का आह्वान किया गया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की, 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का उल्लेख किया, आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) के शीघ्र अंगीकरण का आह्वान किया और आतंकवाद-रोधी संवाद पर सहमति जताई।
- प्रतिनिधिमंडल और सांस्कृतिक बिंदु। प्रधानमंत्री टस्क के साथ लगभग 100 अग्रणी CEOs और उद्योग-प्रतिनिधियों का उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया; दोनों नेताओं ने भारत-पोलैंड व्यापार मंच के स्वागत वक्तव्य में इसका उल्लेख किया। वक्तव्य में वारसौ के गुड महाराजा स्मारक (द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय बच्चों को शरण देने वाले जाम साहेब दिग्विजयसिंहजी की स्मृति) और जाम साहेब स्मारक युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के दो संस्करण (नवीनतम अक्टूबर 2026), ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन से 2,000 से अधिक भारतीय छात्रों की निकासी) का स्मरण, क्राकोव के ज्यागिलोनियन विश्वविद्यालय में ICCR अध्यक्षपीठ, राष्ट्रीय अभिलेखागार सहयोग-समझौता (हस्ताक्षर शेष), V4+भारत विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का स्वागत, पोलैंड को 1 ट्रिलियन डॉलर GDP पार करने पर बधाई, अंतरिक्ष-सहयोग का उत्साह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए पोलैंड-यात्रा का निमंत्रण शामिल हैं।

यह वक्तव्य इरादे, प्रस्ताव और अपेक्षाएँ दर्ज करता है; जिन समझौतों पर "जल्द हस्ताक्षर" या "बातचीत" लिखा है, वे इस वक्तव्य के समय पूरे नहीं हुए थे।

## विश्लेषण

पोलैंड के लिए यह दौरा अर्थव्यवस्था (दोमांस्की के अनुसार 2026 में 3.6 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि के साथ यूरोप की सबसे तेज़ बड़ी अर्थव्यवस्था) और रक्षा-निर्यात दोनों से जुड़ा है। भारत के लिए पोलैंड रूस-यूक्रेन संघर्ष के बदलते यूरोपीय सुरक्षा-परिदृश्य में एक स्वतंत्र साझी के रूप में उपयोगी है, और यह साझेदारी भारत-EU संबंधों (FTA, दिसंबर शिखर सम्मेलन) को भी गति देती है। साथ ही, पोलैंड की रूस-संबंधी संवेदनशीलताएँ (गोपनीयता समझौता) दिखाती हैं कि रक्षा-सहयोग में तकनीक-सुरक्षा और दोहरे-उपयोग वाली वस्तुओं की निगरानी प्रमुख शर्त बन सकती है।

## परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक: भारत-पोलैंड संबंधों की समय-रेखा; रणनीतिक साझेदारी का अर्थ; भारत-EU FTA; पोलैंड का भूगोल (NATO का पूर्वी पक्ष)।

## मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**मुख्य परीक्षा (GS-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध): "भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी भारत की यूरोप-नीति में नया आयाम जोड़ सकती है।" हालिया उच्च-स्तरीय दौरे के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए सहयोग के क्षेत्रों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।** (250 शब्द)

**उत्तर की रूपरेखा:**

**भूमिका में:** संदर्भ दें - पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का 21-23 अक्टूबर 2026 का भारत दौरा (इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 16 वर्षों में किसी पोलिश प्रधानमंत्री का पहला दौरा) और 22 अक्टूबर का संयुक्त वक्तव्य; 1954 के राजनयिक संबंधों और अगस्त 2024 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँची पृष्ठभूमि रखें।

**मुख्य भाग में:** सहयोग के क्षेत्र संयुक्त वक्तव्य के आधार पर रखें - 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य; भारत-EU FTA के शीघ्र हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और समयबद्ध अमल का आह्वान (वार्ता सम्पन्न होना, हस्ताक्षर और अमल अलग चरण हैं - इस अंतर को बरकरार रखें); रक्षा क्षेत्र में संयुक्त कार्य-समूह की 8वीं बैठक (वारसॉ, सितंबर 2026), 'रक्षा उद्योग संवाद' का प्रस्ताव और गोपनीय सूचना संरक्षण समझौता (अभी हस्ताक्षरित नहीं); AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम पर संयुक्त शोध और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता-ज्ञापन (बातचीत के अधीन); पोलैंड का UNSC में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन और IPOI, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, CDRI जैसे मंच। चुनौतियाँ बताएँ - रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पोलैंड की सुरक्षा-संवेदनशीलता (तकनीक-रिसाव और दोहरे-उपयोग वस्तुओं की निगरानी) और दोमांस्की के अनुसार 'विश्वास बनाना' सबसे बड़ा कार्य। प्रेस-रिपोर्टेड तथ्य (जैसे लगभग 6 अरब डॉलर का व्यापार-आँकड़ा या यूक्रेन पर भारत के प्रस्ताव के तीन तत्व) को स्रोत-सीमा के साथ रखें; अधिकारियों ने 'मध्यस्थता' से इनकार किया है।

**निष्कर्ष में:** मूल्यांकन करें - बदलते यूरोपीय सुरक्षा-परिदृश्य में पोलैंड भारत के लिए स्वतंत्र साझी और यूरोपीय बाजारों का संभावित द्वार है, और यह साझेदारी भारत-EU संबंधों को भी गति देती है; परीक्षा इस बात से होगी कि संवाद, निवेश और तकनीकी सहयोग समयबद्ध परिणामों में कितना बदलते हैं।

## स्रोत और सीमाएँ

- [प्राथमिक] PIB, भारत-पोलैंड संयुक्त वक्तव्य, 22 अक्टूबर 2026: लेख खोलें (pib.gov.in)
- [प्राथमिक] PMIndia, भारत-पोलैंड संयुक्त वक्तव्य, 22 अक्टूबर 2026 (पूरा पढ़ा): लेख खोलें (pmindia.gov.in)
- [प्रेस] The Hindu, 22 अक्टूबर 2026 (मोदी-टस्क वार्ता; प्रतिनिधिमंडल, यूक्रेन-प्रस्ताव के तीन तत्व): लेख खोलें (thehindu.com)
- [प्रेस] The Hindu (Business), 23 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरू बिज़नेस फ़ोरम): लेख खोलें (thehindu.com)
- [प्रेस] Indian Express, 2 अक्टूबर 2026: लेख खोलें (indianexpress.com); The Print, 4 अक्टूबर 2026: लेख खोलें (theprint.in)
- [प्रेस] The Hindu, Suhasini Haidar, 21-22 अक्टूबर 2026: लेख खोलें (thehindu.com)
- [प्रेस] Indian Express, Shubhajit Roy (दोमांस्की साक्षात्कार), 22 अक्टूबर 2026: लेख खोलें (indianexpress.com)

सीमा: दोनों प्रेस रिपोर्टें पूरी पढ़ी गईं। विदेश मंत्रालय की घोषणा द हिंदू में उद्धृत रूप से है; मूल विज्ञप्ति अलग से नहीं पढ़ी गई। 1954 राजनयिक संबंध और अगस्त 2024 रणनीतिक साझेदारी दीर्घकालिक दस्तावेज़ित पृष्ठभूमि हैं। ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन (16 दिसंबर) कार्यक्रमित घटना है; उसके परिणाम इस लेख में शामिल नहीं। यूक्रेन-प्रस्ताव संबंधी विवरण केवल प्रेस-स्रोतों पर आधारित है; आधिकारिक दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किया गया। PIB का संयुक्त वक्तव्य (22 अक्टूबर) पूरा पढ़ा गया; ऊपर का नया खंड केवल उसी पर आधारित है। प्रधानमंत्री का अलग प्रेस वक्तव्य (PIB, 22 अक्टूबर) इस अद्यतन में शामिल नहीं है।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

**संक्षिप्त उत्तर:** आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का भारत दौरा 21-23 अक्टूबर था।

### प्रश्न: संयुक्त वक्तव्य के अनुसार डोनाल्ड टस्क का भारत दौरा कब हुआ?

आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का भारत दौरा 21-23 अक्टूबर था। पुराने कार्यक्रम-संदर्भ को सम्पन्न दौरे की पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ना चाहिए, आगामी कार्यक्रम के रूप में नहीं।

**प्रश्न: भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता और उसके अमल में क्या अंतर है?**

भारत-EU FTA की स्थिति: वक्तव्य 27 जनवरी 2026 के भारत-EU शिखर सम्मेलन के संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता सम्पन्न होने का उल्लेख करता है और उसके शीघ्र हस्ताक्षर, अनुसमर्थन तथा समयबद्ध अमल का आह्वान करता है। वार्ता सम्पन्न होना, हस्ताक्षर होना और अमल में आना अलग चरण हैं।

**प्रश्न: भारत-पोलैंड द्विपक्षीय व्यापार के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?**

व्यापार का लक्ष्य, आधार-राशि नहीं: 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य आधिकारिक वक्तव्य में है। नीचे का लगभग 6 अरब डॉलर का आँकड़ा पुरानी प्रेस-रिपोर्ट का है; उसे इस वक्तव्य से स्वतंत्र रूप से पुष्ट मौजूदा आधार-राशि नहीं माना गया है।